RNI No.: UPHIN/25/A1697
GARVI GUJARAT
गरवी गुजरात
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक
वर्ष : 01
अंक : 262
दि. 23.01.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

अमेरिकी टैरिफ तनाव के बीच पीएम ने लूला दा सिल्वा से बात की, जल्द भारत आएंगे ब्राजील के राष्ट्रपति

नई दिल्ली, (जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा से बात की। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक दक्षिण के साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों में करीबी सहयोग बहुत जरूरी है। एक्स एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, मैं जल्द ही ब्राजील के राष्ट्रपति का भारत में स्वागत करने का इंतजार कर रहा हूं।

पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रपति लूला से बात करके खुशी हुई। हमने भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी में मजबूत गति की समीक्षा की, जो आने वाले साल में नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा, वैश्विक दक्षिण के साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए हमारा करीबी सहयोग बहुत जरूरी है।

सरकारी बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और आने वाले साल में इसे और ऊंचाइयों पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। पिछले साल ब्रासीलिया और साउथ अफ्रीका में हुई अपनी मुलाकातों को याद करते हुए, दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, तकनीक, रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र सहित द्विपक्षीय सहयोग के अलग-अलग क्षेत्रों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर संतोष जताया।

भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर बैठक की अध्यक्षता करने वाला है और इसमें शामिल होने के लिए अन्य शासनाध्यक्षों के अलावा लूला दा सिल्वा भी आने वाले हैं। लूला ने पिछले अगस्त में पुष्टि की थी कि 2026 की शुरूआत में भारत का राजकीय दौरा होगा। उन्होंने था कि वह ट्रंप द्वारा लगाए गए टैक्स से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के समूह के बीच बातचीत शुरू करेंगे। यह बात दोनों नेताओं के बीच ऐसे समय हो रही है, जब राष्ट्रपति ट्रंप दावोस में बोर्ड ऑफ पीस की नींव रख रहे हैं।

ये भी पढ़ें: दोबारा राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप की मोटी कमाई: दूसरे कार्यकाल के पहले साल में ही कमाए 1.4 अरब डॉलर, यह है तरीका

ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' से भारत ने बनाई दूरी, हस्ताक्षर समारोह में नहीं हुआ शामिल

वहीं दूसरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पेश किए गए 'बोर्ड ऑफ पीस' के हस्ताक्षर समारोह में भारत शामिल नहीं हुआ।

यह पहल दावोस में विश्व आर्थिक मंच के इतर आयोजित की गई थी और इसका उद्देश्य गाजा में स्थायी शांति की दिशा में काम करना बताया गया है।

भारत के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, जर्मनी सहित कई प्रमुख देश भी हस्ताक्षर समारोह में मौजूद नहीं थे। वहीं जर्मनी, इटली, पराग्वे, रूस, स्लोवेनिया, तुर्किये और यूक्रेन जैसे कुछ देशों ने निमंत्रण पर अब तक स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था, लेकिन भारत ने अब तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा- सनातन को भीतर से खोखला कर रहे 'कालनेमि', ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी

'संत का स्वाभिमान उसका राष्ट्र', शंकराचार्य विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का आया पहला बयान

(जीएनएस)।

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं है. चार करोड़ लोगों ने 18 तारीख को माघ मेले से स्नान किया।

ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन स्नान को लेकर हुए विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी

आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कहा कि एक योगी, एक संत के लिए, एक सन्यासी के लिए धर्म व राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता, उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती.

सोनीपत पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि एक संत के लिए धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान होता है. कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे बहुत कालनेमि होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे, हमें उनसे सतर्क रहना होगा. किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं है. चार करोड़ लोगों ने 18 तारीख को माघ मेले से स्नान किया.

दावोस में दूसरे दिन भी भारत की विकास गाथा पर विमर्श जारी

गंभीर संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित, भारत की सुधार गति मजबूती से सही रास्ते पर है: अश्विनी वैष्णव

उच्च विकास दर और आर्थिक लचीलेपन के कारण भारत विश्व स्तर पर भरोसेमंद देश के रूप में स्थापित

(जीएनएस)।

रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि भारत की सुधार गति मजबूती के साथ सही रास्ते पर है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्देशित गंभीर संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्च विकास दर वाली, लचीली और विश्व स्तर पर भरोसेमंद गंतव्य में बदल दिया है।

दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि हाल के वर्षों में किए गए ऐतिहासिक सुधार सभी क्षेत्रों

में निवेशकों का मजबूत विश्वास पैदा कर रहे हैं।

इन सुधारों में श्रम संहिता सुधार, वस्तु एवं सेवा कर का सरलीकरण, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और परमाणु ऊर्जा को निजी क्षेत्र के लिए खोलना शामिल है।

श्री वैष्णव ने कहा कि सुधार की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निरंतर चल रही है। उन्होंने कहा कि निवेशक भारत में नीतिगत वातावरण से बहुत उत्साहित हैं और अपने निवेश को लगातार बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कई उदाहरण दिए, जिनमें आईकेईए द्वारा अपने निवेश को दोगुना करने की योजना की घोषणा और क्वालकॉम द्वारा भारत में अपने कर्मचारियों की संख्या में काफी विस्तार करना शामिल है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों की कंपनियाँ मौजूदा समय को भारत में निवेश करने के लिए उपयुक्त समय के रूप में देख रही हैं।

भारत के वृहत आर्थिक बुनियादी कारकों की जानकारी देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। देश की अर्थव्यवस्था में अगले पाँच वर्षों में 6-8 प्रतिशत की लगातार विकास दर का अनुमान है।

प्रधानमंत्री मोदी 'इंडिया एनर्जी वीक' का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे

पणजी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 से 30 जनवरी के बीच दक्षिण गोवा में आयोजित होने वाले 'इंडिया एनर्जी वीक' (आईईडब्ल्यू) 2026 सम्मेलन का वीडियो लिंक के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री के महानिदेशक गुरमीत सिंह ने बृहस्पतिवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दक्षिण गोवा जिले के बेतुल गांव में आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, संयुक्त अरब अमीरात के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ सुल्तान अहमद अल जाबेर, कनाडा के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री टिम हॉजसन के साथ-साथ अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और ग्लोबल साउथ के वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की झांकी में भारत की कहानी कहने की परंपराओं और वेव्स के विजन को दिखाया जाएगा

ओम से एल्गोरिदम तक, झांकी राष्ट्र की फलती-फूलती रचनात्मक अर्थव्यवस्था को दर्शाएगी

(जीएनएस)।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की झांकी, "भारत गाथाः श्रुति, कृति, दृष्टि," कहानी कहने की कला में भारत की सभ्यतागत यात्रा की शक्तिशाली दृश्य कहानी प्रस्तुत करेगी। इसमें प्राचीन मौखिक परंपराओं से लेकर वैश्विक कंटेंट और मीडिया पावरहाउस के रूप में इसके उदय तक की पूरी यात्रा दर्शाई जाएगी। यह झांकी आत्मनिर्भर भारत की भावना को दशार्ती है, जो सांस्कृतिक विरासत को तकनीकी नवाचार के साथ सहज रूप से मिलाती है।

श्रुति भारत की समृद्ध मौखिक विरासत का प्रतीक है, जिसे पीपल के पेड़ के नीचे शिष्यों को ज्ञान देते हुए गुरु के माध्यम से दशार्या गया है। इसके साथ ही ओम की ब्रह्मांडीय

अनुगूंज और ज्ञान की उत्पत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले ध्वनि-तरंग रूपांकनों को भी प्रदर्शित किया गया है।

कृति लिखित अभिव्यक्ति के विकास को चिह्नित करती है, जिसमें भगवान गणेश महाभारत लिख रहे हैं। इसे पांडुलिपियों, प्रदर्शन कलाओं और शुरूआती संचार परंपराओं के दृश्यों के माध्यम से भी दिखाया गया है जिन्होंने भारत की बौद्धिक विरासत को आकार दिया।

दृष्टि प्रिंट, सिनेमा, टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भारत के मीडिया के विकास को दिखाती है। विंटेज कैमरे, फि ल्म रील, सैटेलाइट, अखबार और बॉक्स ऑफि स जैसे विजुअल एलिमेंट उन फि ल्म निमार्ताओं और कलाकारों की पीढ़ियों को सम्मान देते हैं जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया है। यह झांकी एआई, अश्ऋ्रह्ल-फ और वर्चुअल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के जरिए भविष्य के लिए तैयार कहानी कहने पर भी जोर देती है, जो इमर्सिव स्टोरीटेलिंग की ओर बदलाव को दिखाती है।

कलाकार इस झांकी को जीवंत बनाते हैं। यह थीम भारत को एक ग्लोबल कंटेंट हब के रूप में स्थापित करने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लक्ष्य से मेल खाती है।

गृहमंत्री अमित शाह ने माता भगवती देवी शर्मा जी की जन्म शताब्दी एवं अखंड दीप शताब्दी वर्ष पर गायत्री परिवार द्वारा आयोजित 'शताब्दी वर्ष समारोह - 2026' को संबोधित किया

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के हरिद्वार में परम वंदनीया माता भगवती देवी शर्मा जी की जन्म शताब्दी एवं अखंड दीप शताब्दी वर्ष पर गायत्री परिवार द्वारा आयोजित 'शताब्दी वर्ष समारोह - 2026' को संबोधित किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि हरिद्वार आस्था, अध्यात्म और संस्कृति का संगम स्थल है और आज 'अखंड ज्योति सम्मेलन' में आकर अखंड ऊर्जा और चेतना की अनुभूति कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पं श्रीराम शर्मा जी ने आस्था, अध्यात्म और संस्कृति से व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण से युग निर्माण की संकल्पना रखी। उन्होंने हर व्यक्ति के अंदर बसी परमात्मा रूपी आत्मा को जागृत और ऊजार्वान करने का कार्य किया है। श्री शाह ने यह कहा कि जो लोग सनातन धर्म को जानते हैं,

भारतीय संस्कृति को समझते हैं और भारत के इतिहास से परिचित हैं, उन्हें दृढ़ विश्वास है कि विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान यदि किसी एक जगह है, तो वह भारतीय परंपरा में ही है।

श्री अमित शाह ने कहा कि आध्यात्मिक रूप से भारत का पुनर्निर्माण केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी होगा। स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि अरविंद जी और पूजनीय पंडित राम शर्मा जी जैसे सभी महान द्रष्टाओं ने अपनी ओजस्वी वाणी में यह विश्वास व्यक्त किया है कि जब भारत अपने पूर्ण तेज के साथ जागृत होगा, तो वह पूरे विश्व को और समस्त ब्रह्मांड को तेजोमय बना देगा। श्री शाह ने कहा कि ऐसे महान मनुष्यों और द्रष्टाओं की वाणी कभी विफल नहीं होती। उनके मुख से निकले सत्य वचनों को हम सभी को ब्रह्मा का वचन मानकर ही आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि पंडित श्री राम शर्मा जी ने गायत्री मंत्र के माध्यम से भक्ति को मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकालकर आम लोगों के मुख और आत्मा तक पहुँचाने का कार्य किया।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि युगदृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और वंदनीय माता भगवती देवी ने अपने जीवनकाल में ही अनेक युगों का कार्य करके दिखाया है। उन्होंने एक ऐसा वटवृक्ष बनाया, जिसकी छाया में आज 100 से अधिक देशों के 15 करोड़ से ज्यादा अनुयायी अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए अपनी आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129 वीं जयंती मनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय आयोजित करेगा 'पराक्रम दिवस- 2026'

भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय, भारत के सबसे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और विरासत से जुड़े देश भर के 13 अन्य प्रतिष्ठित स्थानों के साथ-साथ, 23 से 25 जनवरी 2026 तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के श्री विजय पुरम में 'पराक्रम दिवस-2026' का आयोजन कर रहा है।

वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव

(जीएनएस)।

भारत अपने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव देश भर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक गायन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मिलिट्री बैंड प्रदर्शन के माध्यम से मना रहा है। इस उत्सव का उद्देश्य राष्ट्रीय गौरव और एकता को बढ़ावा देना है।

इन समारोहों के एक अंग के रूप में भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के 31 संगीतकारों से युक्ँ त बैंड ने 21 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के राजीव चौक स्थित एम्फीथिएटर में प्रदर्शन किया। 45 मिनट की इस प्रस्तुति में ब्रास, बांसुरी, स्ट्रिंग और इलेक्ट्रॉनिक वाद्ययंत्रों से ग्यारह मनमोहक धुनें प्रस्तुत की गईं। इस प्रस्तुति में 'वंदे मातरम' और 'सिंदूर' गीत, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता को याद करने के लिए तैयार किया गया था, प्रस्तुति के मुख्य आकर्षण रहे।

संगीत सदियों से भारतीय संस्कृति का एक अनमोल रत्न रहा है। यह भारत की समृद्ध सैन्य विरासत का भी अभिन्न अंग है, जो एकता को सुदृढ़ करता है और वीरता की प्रेरणा देता है। 1944 में अपनी स्थापना के बाद से भारतीय वायु सेना बैंड, भारतीय और पश्चिमी संगीत की विविधतापूर्ण प्रस्तुतियों के साथ, देश की सैन्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। भारतीय वायु सेना बैंड का उद्देश्य अपने मनमोहक प्रदर्शनों के माध्यम से देशभक्ति की भावना को प्रेरित करना और एकता का प्रसार करना है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जिलों के प्रशासनिक तंत्र को स्थानीय प्रस्तुतियों पर नागरिकोन्मुखी निर्णय लेकर समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए स्पष्ट निर्देश दिए

जनवरी - 2026 के राज्य स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम में 110 प्रस्तुतियां, जिला स्वागत कार्यक्रम में 1,492 तथा तहसील स्वागत कार्यक्रम में 2,565 सहित कुल 4,057 प्रस्तुतियों पर कार्रवाई की गई

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की किसानों और सामान्य नागरिक परिवारों की समस्याओं के समाधान के प्रति विशिष्ट संवेदनशीलता

गांधीनगर, 22 जनवरी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जनवरी-2026 के राज्य स्वागत में आई प्रस्तुतियों को प्रत्यक्ष रूप से सुनकर सार्वजनिक रास्तों पर किए गए अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण, ड्रेनेज और नालों में किए गए अवैध अतिक्रमण, तथा एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले मार्गों पर किए गए अतिक्रमण से संबंधित राज्य स्वागत कार्यक्रम की प्रस्तुतियों पर नागरिकोन्मुखी निर्णय लेते हुए समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए।

हर महीने के चौथे गुरुवार को आयोजित 'स्वागत ऑनलाइन' जन शिकायत निवारण कार्यक्रम अंतर्गत जनवरी-2026 के राज्य-स्वागत में

राज्य भर से 110 से अधिक प्रस्तुतिकर्ता अपनी प्रस्तुतियों के साथ उपस्थित हुए। इसके अतिरिक्त, जिला स्वागत कार्यक्रम की 1,492 तथा तहसील स्वागत कार्यक्रमकी 2,565 प्रस्तुतियों/प्रश्नों के संदर्भ में भी जिला एवं तहसील स्तर पर समाधान की कार्रवाई की गई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के समक्ष इस राज्य स्वागत कार्यक्रम में डभोई तथा बोटाद जिलों के किसानों द्वारा की गई प्रस्तुतियों तथा सूरत जिले में गुजरात हाउसिंग बोर्ड के जर्जर मकानों के स्थान पर नए मकानों के निर्माण से संबंधित लंबे समय से लंबित प्रश्न की प्रस्तुति पर उन्होंने त्वरित एवं संवेदनशील प्रतिसाद दिया।

मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासनिक तंत्र को स्पष्ट निर्देश दिए कि डभोई नगरपालिका के गटर के पानी के कारण 33 किसानों की लगभग 150 बीघा कृषि योग्य भूमि की फसलों को नुकसान न हो तथा भूमि खराब न हो, इसके लिए तात्कालिक रूप से सायफन बनाने और नगरपालिका का एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) सुचारु रूप से कार्य करे तथा किसानों की इस दीर्घकालीन समस्या का समाधान हो।

मुख्यमंत्री के समक्ष बोटाद जिले के किसानों ने यह प्रस्तुति रखी कि गांव के तालाब की पाल की ऊंचाई बढ़ाने के परिणामस्वरूप 42 किसानों की लगभग 500 बीघा भूमि डूब में चली जाती है तथा खेतों में आवागमन का मार्ग बंद हो गया है।

श्री भूपेंद्र पटेल ने तुरंत किसान हितोन्मुखी निर्णय लेकर इस समस्या के त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभाग और स्थानीय प्रशासनिक तंत्र को निर्देश दिए।

राज्य स्वागत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष किसानों के इन प्रश्नों के अतिरिक्त, सूरत जिले में गुजरात हाउसिंग बोर्ड के जिन जर्जर मकानों को गिरा दिया गया है, उनके स्थान पर नए मकानों के निर्माण से संबंधित लंबे समय से लंबित प्रस्तुति भी लाभार्थियों द्वारा की गई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इन प्रस्तुतियों के संदर्भ में गुजरात हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को नए आवासों के निर्माण की प्रक्रिया शीघ्रता से पूर्ण करने के दिशानिर्देश भी दिए।

जनवरी -2026 के इस राज्य स्वागत में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, सचिव श्री अजय कुमार, विशेष कार्याधिकारी श्री डी. के. पारेख, श्री राकेश व्यास तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सम्पादकीय

गाजा संघर्षो के समाधान पर काम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में स्थायी शांति स्थापित करने और वैश्विक स्तर पर संघर्षो का समाधान करने की दिशा में काम करने के लिए स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में बृहस्पतिवार को शांति बोर्ड का घोषणा पत्र लांच करते हुए कहा कि यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर न मात्र पमि एशिया में बल्कि अन्य जगहों पर भी युद्धों को सुलझाने में मदद कर सकता है।

राष्ट्रपति ट्रंप की प्रवृत्ति को देखते हुए यह बोर्ड वुछ भी हो सकता है किन्तु शांति के लिए कितना काम करेगा, इस पर तो विवाद रहेगा ही।

राष्ट्रपति ट्रंप खुद ही न मात्र शांति के दुश्मन हैं बल्कि वह उन देशों के हितैषी हैं जो आतंकवाद के प्रयोजक, रक्षक और पोषक हैं तथा शांति के दुश्मन हैं। ट्रंप ने इस शांति बोर्ड में पाकिस्तान जैसे दुष्ट देश को रखा है जिसकी सेना ने अपने पड़ोसियों को तंग करने के लिए अपनी सुरक्षा नीति को ही आतंकी बना रखा है।

जो देश इस शांति बोर्ड में शामिल हो चुके हैं उनमें अजेटींना, आम्रेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस, मिरत्र, हंगरी, कजाकिस्तान, मोरक्को, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और वियतनाम शामिल हैं। ये देश हमास के हथियार छीनेंगे और उसे किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने से रोवेंगे। दूसरी तरफ दुनिया के वे देश जो न सिर्प रक्षा क्षेत्र में मजबूत हैं बल्कि आर्थिक ताकत हैं उन्होंने ट्रंप के निमंत्रण पर विशेष ध्यान न देते हुए इस बोर्ड की सार्थकता के प्रति ही अपना विश्वास व्यक्त नहीं किया। इसलिए भारत के अलावा प्रंस, ब्रिटेन, चीन, जर्मनी और कई अन्य महत्वपूर्ण देश अनावरण समारोह में शामिल नहीं हुए। पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, अजरबैजान जैसे मुस्लिम देशों की तो मजबूरी है कि वे गाजा की शांति प्रव्रिया में शामिल हों ताकि उनकी इस्लामिक राजनीति की प्रसंगिकता बनी रहे। किन्तु जो भी देश समझ का परिचय देंगे वे इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर आंख मूंद कर ट्रंप जैसे अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करने की गलती नहीं करेंगे। दुनिया यदि संयुक्त राष्ट्र संघ की वैकल्पिक संस्था शांति बोर्ड को मानने को तैयार हो जाए तो आखिर दो संस्थाओं की जरूरत ही क्या है? यूएन तो वैसे ही अप्रसंगिक संस्था हो चुका है ऐसे में उस देश की चौधराहट में शांति बोर्ड क्या भूमिका निभाएगा जो राजनीतिक रूप से स्थिर देशों को अस्थिर एवं शांति व समृद्ध देशों को मात्र अपने स्वार्थ के लिए अशांत और दरिद्र बनाने का षडांत्र करता है. किसी देश के चुने हुए राष्ट्रपति को अगवा करने वाला व्यक्ति शांति के प्रति कितना समर्पित होगा, इसका आंकलन बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है।

सच तो यह है कि ट्रंप हमेशा सभी राष्ट्राध्यक्षों को पहले सुगर कोटेड जहरीली गोली देते हैं लेकिन जब उनका षडांत्र सफल नहीं होता तब वह धमकी देने पर उतर आते हैं। लेकिन यदि किसी देश का शासनाध्यक्ष उनकी धमकी को गंभीरता से नहीं लेता तो वह वुटिलता पर उतर आते हैं और उस नेता को बदनाम करने के उद्देश्य से गोपनीय वाताओं को तोड़- मरोड़ कर मीडिया में लीक कर देते हैं या सार्वजनिक कर देते हैं।

बहरहाल शांति के प्रति समर्पण यदि ट्रंप का संकल्प है तो इसका मतलब है कि वह ढोंग कर रहे हैं। इस तरह के शांति बोर्ड की स्थापना करना मात्र यूएनओ का ही दायित्व है। इसलिए लगता नहीं कि यूएनओ की भूमिका ट्रंप का शांति बोर्डा निभा पाएगा। ट्रंप ने दिखावे के लिए शांति बोर्ड का गठन किया है। ट्रंप का उद्देश्य है कि किसी तरह शांति नोबेल पुरस्कार प्रप्त कर लें, भले ही उन्हें इसके लिए अपने स्वाभाविक चरित्र के प्रतिवूल दिखावा ही न करना पड़े। यह संतोष का विषय है कि भारत तो ट्रंप के हर कदम का सही मूल्यांकन करता ही है, साथ ही उसने शांति बोर्ड में शामिल होने की जल्दबाजी से बचा रहा।

गणतंत्र दिवस 2026: डीआरडीओ कर्तव्य पथ और भारत पर्व में अपने पथ-प्रदर्शक नवाचारों का प्रदर्शन करेगा

(जीएनएस)।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) कर्तव्य पथ और भारत पर्व 2026 में 77वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपने कुछ पथ-प्रदर्शक नवाचारों का प्रदर्शन करेगा। ये प्रणालियां हैं: लंबी दूरी की एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल (एलआर-एएसएचएम) और डीआरडीओ झांकी- 'कॉम्बैट सबमैनिन्स के लिए नौसेना प्रौद्योगिकियां'।

कर्तव्य पथ पर एलआर-एएसएचएम

डीआरडीओ परेड के दौरान लॉन्चर के साथ एलआर-एएसएचएम का प्रदर्शन करेगा। इस हथियार प्रणाली को भारतीय नौसेना की तटीय बैटरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। एलआर-एएसएचएम एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो स्थिर और गतिशील लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है और इसे विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम और उच्च सटीकता सेंसर पैकेज के साथ अपनी तरह की पहली मिसाइल है।

यह हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 10 से शुरू होने वाली हाइपरसोनिक गति के साथ एक अर्ध-बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करती है और कई स्किप के साथ औसत मच 5.0 को बनाए रखती है। टर्मिनल चरण में गतिशील लक्ष्यों को भेदने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सेंसर प्रदान किए जाते हैं। चूंकि यह मिसाइल कम ऊंचाई पर तेज गति और गतिशीलता के साथ उड़ती है, इसलिए दुश्मन के जमीन और जहाज आधारित रडार इस मिसाइल के अधिकांश प्रक्षेपवक्र के दौरान इसका पता नहीं लगा सकते हैं।

एलआर-एएसएचएम को दो चरण ठोस प्रणोदन रॉकेट मोटर प्रणाली के साथ कॉनफि गर किया गया है। ये प्रणोदन प्रणालियाँ मिसाइल को आवश्यक हाइपरसोनिक वेगों तक बढ़ाती हैं। वाहन के खर्च होने के बाद उसके स्टेज-1 को अलग कर दिया जाता है। स्टेज- क्क बर्नआउट के बाद, वाहन लक्ष्य को भेदने से पहले वातावरण में आवश्यक युद्धाभ्यास के साथ एक बिना शक्ति वाला ग्लाइड करता है।

भारत पर्व में डीआरडीओ की झांकी

इस वर्ष, डीआरडीओ की झांकी 26 से 31 जनवरी, 2026 तक लाल किले के भारत पर्व में प्रदर्शित की जाएगी। झांकी का विषय 'लड़ाकू पनडुब्बियों के लिए नौसेना प्रौद्योगिकियां' है, जो स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों/प्रणालियों को प्रदर्शित करेगा जो भारतीय नौसेना की पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए बल गुणक के रूप में कार्य करती हैं। ये प्रणालियां इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सूट (आईसीएस), वायर गाइडेड हैवी वेट टॉरपीडो (डब्ल्यूजीएचडब्ल्यूटी) और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन हैं जो पानी के नीचे के क्षेत्र में युद्ध वर्चस्व सुनिश्चित करेंगी।

आईसीएस पानी के नीचे युद्ध और पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए महत्वपूर्ण नई पीढ़ी की पनडुब्बी आधारित रक्षा प्रणाली है। यह प्रणालियों की एक प्रणाली है जो हथियार चयन, लॉन्च और मार्गदर्शन जैसे सामरिक निर्णय और कार्यों को करने के लिए खतरे की तस्वीर प्रदान करके अद्वितीय स्थितिजन्य जागरूकता देती है। आईसीएस पूरे भारत में लगभग 150 प्रमुख उद्योग भागीदारों और एमएसएमई की सक्रिय भागीदारी के साथ डीआरडीओ की आठ प्रयोगशालाओं का एक सहयोगात्मक प्रयास है।

डब्ल्यूजीएचडब्ल्यूटी समुद्री जल में समकालीन जहाज और पनडुब्बी खतरों का मुकाबला करने के लिए एक अत्याधुनिक पनडुब्बी द्वारा प्रक्षेपित टारपीडो है। इसे पनडुब्बी रोधी युद्ध के परिदृश्य में एक घातक हथियार माना जाता है और यह सभी पनडुब्बियों का प्राथमिक हथियार है। भारतीय नौसेना देश भर में समुद्र के विशाल हिस्से में ब्लू वाटर नौसैनिक युद्ध और रणनीतिक लाभ में प्रभुत्व बनाए रखने के लिए अपने पनडुब्बी बेड़े का लगातार विस्तार कर रही है। इसे प्राप्त करने के लिए, इसे उच्च गति और सहनशक्ति के साथ स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी लॉन्च एंटी-शिप, एंटी-सबमरीन हैवीवेट टॉरपीडो की आवश्यकता है।

एआईपी पनडुब्बियों के लंबे समय तक पानी के नीचे सहनशक्ति के लिए है, इस प्रकार स्टील्थ को बढ़ाता है। यह स्थानीय रूप से विकसित फॉस्फोरिक एसिड ईंधन सेल द्वारा संचालित है जिसमें एक नया ऑनबोर्ड हाइड्रोजन जनरेटर है। एआईपी प्रणाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को खिलाकर फॉस्फोरिक एसिड ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करती है। कंडीशनिंग के बाद ईंधन सेल जनित बिजली पनडुब्बी बिजली लाइन के ऊपर खिलाया जाता है और पनडुब्बी बिना कोई शोर किए चुपचाप पानी के नीचे चलती है। इस प्रकार विकसित की गई तकनीक

भारतीय वायु सेना ने गणतंत्र दिवस 2026 के प्रेस पूर्वावलोकन में युद्धक क्षमता, वीरतापूर्ण धुनों और पूर्व सैनिकों की विरासत की झलक पेश की

(जीएनएस)।

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने आज, 22 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस परेड (आरडीपी) के लिए अपना प्रेस पूर्वावलोकन आयोजित किया। इस दौरान कर्तव्य पथ पर होने वाले राष्ट्रीय समारोहों के मुख्य आकर्षणों—मार्चिंग दस्ते, पूर्व सैनिकों की झांकी और फ्लाईपास्ट का विस्तृत विवरण साझा किया गया।

मीडिया को जानकारी देते हुए भारतीय वायु सेना ने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो भारत की सैन्य शक्ति और तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करता है। भारतीय वायु सेना के आदर्श वाक्य "नभः स्पृशं दीप्तम" के अनुरूप, परेड के सभी घटक राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के साथ-साथ देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति वायु सेना की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करेंगे।

इस वर्ष भारतीय वायु सेना, गणतंत्र दिवस समारोह से जुड़े सभी औपचारिक कार्यक्रमों के संचालन के लिए लीड सर्विस की भूमिका निभा रही है। गणतंत्र दिवस परेड के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित होने वाला भव्य गार्ड ऑफ ऑनर, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी शहीद नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उसका नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर हेमंत सिंह कात्याल द्वारा किया जाएगा।

मीडिया ब्रीफिंग की शुरूआत भारतीय वायु सेना के मार्चिंग दस्ते के परिचय के साथ हुई, जो परंपरा और आधुनिकता के एक विशिष्ट संगम का प्रतिनिधित्व करेगा। सेना की विभिन्न इकाइयों से अपनी उत्कृष्ट सैन्य मुद्रा के आधार पर चुने गए 144 युवा वायु योद्धाओं से बना यह दस्ता, गर्व और

गौरव की विरासत को सम्मानित करने के साथ-साथ भारतीय वायु सेना के मूल मूल्यों को दृढ़ता से बनाए रखने के लिए हफ्तों के कठोर प्रशिक्षण से गुजरा है। भारतीय वायु सेना के इस मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर जगदीश कुमार कर रहे हैं, जिनके साथ स्क्वाड्रन लीडर निकिता चौधरी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रखर चंद्राकर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिनेश सुपरन्यूमेररी अधिकारियों के रूप में शामिल हैं।

भारतीय वायु सेना बैंड, जिसका नेतृत्व सार्जेंट चार्ल्स एंटनी डेनियल करेंगे, मार्चिंग दस्ते का उत्साहवर्धन करेगा। इस बैंड में 72 बेहतरीन म्यूज़िशियन शामिल हैं, जिनमें 57 अग्निवीरवायु और 9 महिला अग्निवीरवायु (जिन्हें पहली बार शामिल किया जा रहा है) के साथ 3 ड्रम मेजर भी हिस्सा लेंगे। जब यह बैंड राष्ट्रपति के सलामी मंच के सामने से गुजरेगा, तब यह "साउंड बैरियर" धुन बजाएगा, जो वायु सेना की बहुमुखी प्रतिभा और इसके आधुनिक स्वरूप को प्रदर्शित करेगी।

मीडिया ब्रीफिंग का मुख्य आकर्षण इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारतीय वायु सेना द्वारा प्रस्तुत पूर्व सैनिकों की झांकी के विषय "संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक" का अनावरण था। झांकी के अगले हिस्से में अमर जवान ज्योति और ऐतिहासिक युद्ध मशीनों के 3ऊ मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें ळ-55 और विजयंत टैंक, हंटर, मिग-21, मिराज और जगुआर विमान, तथा आईएनएस मैसूर और आईएनएस राजपूत शामिल हैं। इसके साथ ही इसमें 1965 और 1971 के युद्धों और 1999 के कारगिल ऑपरेशन विजय के चित्रण भी शामिल हैं। झांकी का पिछला हिस्सा राष्ट्रीय विकास में पूर्व सैनिकों की भूमिका पर प्रकाश डालता है, जिसमें बाढ़ राहत, चिकित्सा सेवाओं, शिक्षा और 'मेक इन इंडिया' पहल में उनके स्वैच्छिक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

मीडिया ब्रीफिंग का समापन इस वर्ष के फ्लाईपास्ट पर एक प्रस्तुति के साथ हुआ, जिसमें छह अलग-अलग हवाई अड्डों से संचालित होने वाले 29 विमान शामिल होंगे। इनमें 16 लड़ाकू विमान, 4 परिवहन विमान और 9 हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे। आठ अलग-अलग फॉर्मेशन में व्यवस्थित यह फ्लाईपास्ट 'ध्वज' फॉर्मेशन के साथ शुरू होगा, जिसमें चार द्ट-17 क्श हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज के साथ तीनों सेनाओं के झंडे लेकर उड़ान भरेंगे। इस प्रदर्शन में राफेल, सुखोई-30 टङ्क, मिग-29 और जगुआर विमानों की क्षमताओं को दिखाया जाएगा, जिन्हें उ-130 और उ-295 जैसे स्ट्रेटेजिक विमानों और भारतीय नौसेना के ढ-8 एयरक्राफ्ट भी शामिल होंगे। संयुक्त कौशल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय वायु सेना के अछ्ल टङ क्श और भारतीय सेना के अछ्ल हरक् अपाचे तथा प्रचंड (एलएचसी) जैसे हमलावर हेलीकॉप्टर भी फ्लाईपास्ट में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण "ऑपरेशन सिंदूर" फॉर्मेशन है, जो वायु शक्ति और सटीकता का प्रदर्शन करेगा। यह भारतीय वायु सेना के इस वर्ष की थीम "अचूक, अभेद्य व सटीक" को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगा।

प्रेस पूर्वावलोकन ने भारतीय वायु सेना की एक युद्ध-क्षमता, सुगठित बल और राष्ट्र के एक अटल स्तंभ के रूप में उसकी स्थिति को रेखांकित किया।

सरकार ने 208 अन्य कार्बन-गहन उद्योगों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन गहनता लक्ष्य अधिसूचित किए

(जीएनएस)।

भारत सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) के तहत अतिरिक्त कार्बन-गहन क्षेत्रों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन गहनता (जीईआई) लक्ष्य अधिसूचित किए हैं। 13.01.2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, वस्त्र उद्योग और द्वितीयक एल्युमीनियम को भारतीय कार्बन बाजार (आईसीएम) के अनुपालन तंत्र के तहत लाया गया है।

इन क्षेत्रों में कुल 208 बाध्य संस्थाओं को अब निर्दिष्ट उत्सर्जन तीव्रता में कमी के लक्ष्यों को पूरा करना होगा। इस विस्तार के साथ, आईसीएम का अनुपालन तंत्र अब भारत के सबसे अधिक उत्सर्जन-गहन उद्योगों में 490 बाध्य संस्थाओं को कवर करता है। भारत सरकार ने सबसे पहले अक्टूबर 2025 में एल्युमीनियम, सीमेंट, क्लोर-अल्कली और पल्प एंड पेपर क्षेत्रों के लिए जीईआई लक्ष्य अधिसूचित किए थे, जिनमें 282 बाध्य संस्थाएं शामिल थीं।

भारत सरकार द्वारा 2023 में अधिसूचित सीसीटीएस,आईसीएम के कामकाज के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करता है। सीसीटीएस का मकसद कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र व्यापार तंत्र के जरिए उत्सर्जन का मूल्य निर्धारण करके भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना या उससे बचना है।

सीसीटीएस दो तंत्रों के जरिए संचालित होता है: अनुपालन तंत्र और ऑफसेट तंत्र। अनुपालन तंत्र के तहत, उत्सर्जन-प्रधान उद्योगों को बाध्य संस्थाओं के रूप में नामित किया जाता है और उन्हें निर्धारित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (जीईआई) लक्ष्यों को पूरा करना अनिवार्य है। जो बाध्य संस्थाएं अपने लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं, वे कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पात्र होती हैं, जिनका वे उन बाध्य संस्थाओं के साथ आदान-प्रदान कर सकती हैं, जो अपने लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ हैं।

यह प्रगति उद्योगों के साथ वर्षों के निरंतर जुड़ाव, कठोर तकनीकी मूल्यांकन और संस्थानों एवं हितधारकों के बीच समन्वित प्रयासों का नतीजा है। जैसे-जैसे क्षेत्रीय कवरेज गहराता जा रहा है और अनुपालन तंत्र परिपक्व हो रहा है, आईसीएम भारत के दीर्घकालिक जलवायु उद्देश्यों और नेट-जीरो लक्ष्य के साथ औद्योगिक विकास को संरेखित करने में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मूडीज द्वारा एसक्यूएस2 'बहुत अच्छी संवहनीयता गुणवत्ता रेटिंग

22 जनवरी,2026: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के संवहनीय वित्तपोषण ढाँचे पर मूडीज रेटिंग्स द्वारा द्वितीय पक्ष राय (एसपीओ) जारी किया गया है, जिसमें बैंक को एसक्यूएस2 – 'बहुत अच्छी संवहनीयता गुणवत्ताह्व रेटिंग प्रदान की गई है. यह रेटिंग मूडीज के संवहनीयता गुणवत्ता स्कोर (एसक्यूएस) स्केल पर दूसरी सर्वोच्च श्रेणी है, जो संवहनीय एवं जिम्मेदार वित्तपोषण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दशार्ती है.

मूडीज रेटिंग्स द्वारा प्रदान की गई द्वितीय पक्ष राय वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त बेंचमार्क है, जो संवहनीयता ढांचे की विश्वसनीयता एवं सुदृढ़ता का स्वतंत्र भरोसेमंद राय का स्त्रोत है. यह राय निवेशकों एवं हितधारकों के लिए पारदर्शिता को और मजबूत बनाता है तथा यह पुष्टि करता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का संवहनीय वित्तपोषण ढाँचा अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के अनुरूप है और पर्यावरणीय एवं सामाजिक उद्देश्यों में सार्थक योगदान देता है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपनी मुख्य परिचालन एवं वित्तपोषण गतिविधियों में संवहनीयता को एकीकृत करने के अपने मिशन के प्रति दृढ़ है, जो समाज, पर्यावरण तथा आने वाली पीढ़ी के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन करने के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करता है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देश के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंकों में से एक है, जो नवोन्मेषी वित्तीय समाधान प्रदान करने के साथ-साथ संवहनीय विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है.

आईसीएमआर ने असम सरकार को मोबाइल स्ट्रोक यूनिट सौंपा

इससे ग्रामीण, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों तक जीवन रक्षक स्ट्रोक उपचार सुगमता से पहुंचेगा

भारत ग्रामीण क्षेत्रों में इस्केमिक स्ट्रोक से अत्यधिक ग्रसित रोगियों के उपचार के लिए आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के साथ मोबाइल स्ट्रोक यूनिट (एमएसयू) के सफल एकीकरण की रिपोर्ट करने वाला विश्व का दूसरा देश : स्वास्थ्य अनुसंधान सचिव

मोबाइल स्ट्रोक यूनिट से पूर्वोत्तर भारत में स्ट्रोक के उपचार में क्रांति, उपचार का समय 24 घंटे से घटकर अब 2 घंटे, मृत्यु दर में एक तिहाई की कमी और विकलांगता आठ गुना कम हुई

(जीएनएस)।

भारत में स्ट्रोक मृत्यु और दीर्घकालिक विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है। स्ट्रोक की स्थिति में हर मिनट महत्वपूर्ण है—उपचार में देरी होने पर लगभग 1.9 बिलियन मस्तिष्क कोशिकाएं प्रति मिनट नष्ट हो जाती हैं। सही समय पर उपचार मिलने से मृत्यु और आजीवन विकलांगता में अत्यधिक कमी आ सकती है। यद्दिप, स्ट्रोक के उपचार में सबसे बड़ी चुनौती रोगियों को स्ट्रोक के लिए

तैयार अस्पताल तक पहुंचने में लगने वाला समय है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने इस गंभीर समस्या में कमी लाने के लिए असम सरकार को दो मोबाइल स्ट्रोक यूनिट (एमएसयू) सौंपी हैं। यह दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले स्ट्रोक रोगियों के लिए अस्पतालों तक शीघ्र पहुंचने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अब अस्पताल ही सीधे रोगियों तक पहुंचने लगे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा के मार्गदर्शन में विकसित यह पहल, सरकार की इस प्रतिबद्धता को दशार्ती है कि सबसे चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में भी, सबसे निर्धन, वंचित और निर्बल आबादी, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, तक उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचें।

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने असम सरकार को मोबाइल स्ट्रोक यूनिट (एमएसयू) सौंपते हुए कहा, 'मोबाइल स्ट्रोक यूनिट सबसे पहले जर्मनी में विकसित की गई थीं और बाद में प्रमुख वैश्विक शहरों में इनका मूल्यांकन किया गया। भारत ने पूर्वोत्तर भारत के ग्रामीण, दूरस्थ और दुर्गम भूभागों में ऐसी यूनिटों का मूल्यांकन किया है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र इस्केमिक स्ट्रोक के रोगियों के उपचार के लिए आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के साथ एमएसयू के सफल एकीकरण की रिपोर्ट करने वाला विश्व स्तर पर दूसरा देश भी हैं।'

असम सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव एवं आयुक्त श्री पी. अशोक बाबू ने राज्य के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि 'इस हस्तांतरण से असम की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली मजबूत होगी और राज्य में इस जीवन रक्षक सेवा की निरंतरता सुनिश्चित होगी।ह्व उन्होंने कहा कि आईसीएमआर के साथ सहयोग से स्ट्रोक रोगियों के लिए त्वरित उपचार, बेहतर समन्वय और बेहतर परिणाम संभव हुए हैं और विस्तार के लिए एक मजबूत आधार तैयार हुआ है।

एमएसयू एक चलता-फिरता अस्पताल है, जो सीटी स्कैनर, विशेषज्ञों से टेलीकंसल्टेशन, प्वाइंट-ऑफ-केयर प्रयोगशाला और रक्त के थक्के तोड़ने वाली दवाओं से सुसज्जित है। यह रोगी के घर पर या उसके आस-पास ही स्ट्रोक का शीघ्र निदान और उपचार करने में सक्षम बनाता है। यह नवोन्मेषण विशेष रूप से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां अस्पतालों तक पहुंचने में कई घंटे लग सकते हैं। विशेषज्ञ टेलीकंसल्टेशन के माध्यम से, एमएसयू स्ट्रोक के प्रकार की शीघ्र पहचान और उपचार की त्वरित शुरूआत को संभव बनाता है-जिससे जीवन बचता है और विकलांगता को रोका जा सकता है।

पूर्वोत्तर में स्ट्रोक का प्रकोप बहुत अधिक है। दुर्गम भूभाग, लंबी दूरी और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं की सीमित उपलब्धता के कारण हमेशा समय पर स्ट्रोक का उपचार चुनौतीपूर्ण रहा है।

रोहित शर्मा को मिला सबसे बड़ा सम्मान! मैदान पर छक्के छुड़ाने वाले हिटमैन को अब इस नाम से पुकारेगी दुनिया

भारतीय क्रिकेट के 'हिटमैन' रोहित शर्मा के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। मुंबई के अजिंक्य डीवाई पाटिल ने स्वयं रोहित को यह उपाधि दी, जिससे अब खेल जगत के इस दिग्गज के नाम के साथ

अजिंक्य डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय ने भारतीय क्रिकेट में उनके अतुलनीय योगदान और उनके बेमिसाल नेतृत्व के लिए उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है।

मुंबई में आयोजित विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह के दौरान रोहित शर्मा को यह सम्मान प्रदान किया गया। इस ऐतिहासिक पल के दौरान विश्वविद्यालय के चांसलर डॉ. 'डॉक्टर' शब्द भी जुड़ गया है।

यूनिवर्सिटी की प्रतिक्रिया

विश्वविद्यालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि रोहित शर्मा केवल एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि रणनीति और धैर्य के प्रतीक हैं, जो आज की युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ी प्रेरणा हैं। क्रिकेट के मैदान पर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और शांत कप्तानी के लिए मशहूर रोहित ने हाल के वर्षों में भारतीय टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है।

कप्तानी में टीम रही सफल

उनकी कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जैसे बड़े टूर्नामेंट जीतकर दुनिया भर में तिरंगा लहराया है। हालांकि रोहित ने टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन वनडे प्रारूप में वे अब भी टीम इंडिया की मजबूती बने हुए हैं।

फैंस को मिला झूमने का मौका

रोहित शर्मा की इस उपलब्धि ने उनके करोड़ों प्रशंसकों को जश्न मनाने का एक और मौका दे दिया है। सोशल मीडिया पर अक्सर फैंस उनकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करते हैं। रोहित की कप्तानी की सबसे बड़ी खासियत खिलाड़ियों पर भरोसा जताना और कठिन परिस्थितियों में टीम को एकजुट रखना रही है, जिसे अब शिक्षा जगत ने भी एक महान नेतृत्व गुण के रूप में मान्यता दी है।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

विजिलेंस की कार्रवाई से हड़कंप, भूमि के मुआवजे के एवज में 10 हजार की रिश्वत ले रहा अमीन दबोचा

(जीएनएस)।

उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस का एक्शन जारी है। उत्तरकाशी में विजिलेंस की टीम ने लोनिवि के एक अमीन को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। विजिलेंस की टीम ने अभियुक्त को दबोचने के बाद कई घंटे तक पूछताछ की।

साथ ही अमीन की संपत्ति के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। बताया गया कि सड़क निर्माण के दौरान कटान की भूमि के मुआवजे के एवज में अमीन ने घूस मांगी थी। जिसकी शिकायत विजिलेंस को की गई। विजिलेंस ने जांच के बाद आरोपी को रिश्वत लेते दबोच लिया।

विजिलेंस से मिली जानकारी के अनुसार उत्तरकाशी के प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी कैंप कार्यालय में नियुक्त अमीन टिका राम नौटियाल के खिलाफ विजिलेंस को

शिकायत मिली थी। बताया जा रहा है कि अमीन शिकायतकर्ता से सड़क निर्माण के दौरान कटान हुई भूमि के मुआवजे के एवज में रिश्वत मांग रहा था, शिकायतकर्ता ने विजिलेंस में एक सूचना दी थी।

जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि अमीन टिका राम नौटियाल उनसे भूमि के मुआवजे से जुड़ी फाइल को आगे बढ़ाने के एवज में रिश्वत मांग रहा है। विजिलेंस ने शिकायत पर जाल बिछाया। गुरुवार यानी 22 जनवरी को अमीन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस की टीम ने अमीन को पकडने के बाद पूछताछ की और साथ ही सभी दस्तावेज खंगाले गए। उत्तराखंड में विजिलेंस लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

रिश्वतखोर अधिकारी और कर्मचारियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने में जुटी है। बीती 16 जनवरी को भी विजिलेंस की टीम ने हरिद्वार के जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्य और उनके सहायक गौरव शर्मा को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। जो कि राशन डीलर से मांगी गई थी। इससे पहले हरिद्वार जिले के रुड़की में विजिलेंस की टीम ने सिविल अस्पताल से एक डॉक्टर को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। लगातार पूरे प्रदेश में रिश्वतखोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत एक्शन जारी है।

शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी पर हुए अत्याचार मामले में 'आप' प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी की प्रतिक्रिया

शंकराचार्य पर हुआ अत्याचार इखढ द्वारा हिंदू समाज और सनातन धर्म के अपमान के समान : इसुदान गढ़वी

हिंदू समाज और आम आदमी पार्टी शंकराचार्य पर हुए हमले का समर्थन नहीं करती : इसुदान गढ़वी

भाजपा हिंदुत्व के नाम पर सरकारी तंत्र द्वारा हिंसा और दबाव करती है : इसुदान गढ़वी

शंकराचार्य के सम्मान के लिए आम आदमी पार्टी की कानूनी कार्रवाई की मांग : इसुदान गढ़वी

भाजपा पार्टी नहीं, सर्टिफिकेट बेचने वाली कॉर्पोरेट कंपनी बन गई है : इसुदान गढ़वी

शंकराचार्य को स्नान करने से रोकना सनातन परंपरा का अपमान : इसुदान गढ़वी

शंकराचार्य पर हुए अत्याचार मुद्दे पर फ्रर-श्लढ-बजरंग दल से आवाज उठाने की इसुदान गढ़वी की अपील

अहमदाबाद/गुजरात

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंदजी पर हुए अत्याचार मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा पार्टी नहीं, एक कॉर्पोरेट कंपनी है और सबको सर्टिफिकेट बेचने का ठेका ले लिया है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दौरान गत 18/01/2026 को जगद्गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंदजी और उनके शिष्यों पर हुआ अत्याचार हिंदू समाज और सनातन धर्म के लिए चिंता का विषय है। पुलिस और प्रशासन द्वारा शंकराचार्य और उनके शिष्यों को स्नान करने से रोका गया, पालकी रोकी गई, तथा उनके शिष्यों की चोटी पकड़कर जो अत्याचार किया गया है, उससे सभी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ हुआ यह अत्याचार केवल व्यक्तिगत हमला नहीं है, बल्कि हिंदू समाज और सनातन परंपरा के सर्वमान्य मूल्यों पर किया गया घोर प्रहार है। भाजपा अब हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर एक कॉर्पोरेट कंपनी बन गई है। भाजपा गायमाता, हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं से खेलने लगी है। शंकराचार्य से भी हिंदू आस्था का सर्टिफिकेट मांगते हैं ? आप कौन हैं? आप अपने राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र दें। आम आदमी पार्टी ने शंकराचार्य के समर्थन में विभिन्न जगहों पर विरोध दर्ज कराया है।

AAP नेता इसुदान गढ़वी ने आगे कहा कि फ्रर, बजरंग दल, श्लढ से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे शंकराचार्यों पर भाजपा अत्याचार कर रही है, तब आपको भी एकजुट होकर इस शंकराचार्यजी के समर्थन में आवाज उठानी चाहिए।

ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने भारतीय डाक के विकास व कायाकल्प में तेजी लाने के लिए उच्च स्तरीय तीसरी तिमाही बिजनेस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

(जीएनएस)।

डाक विभाग ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय संचार एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री की अध्यक्षता में वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के लिए 'त्रैमासिक बिजनेस समीक्षा बैठक' आयोजित की। इस बैठक में देशभर के वरिष्ठ अधिकारियों और सर्किलों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया, ताकि प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों के प्रदर्शन की समीक्षा की जा सके और विकास को गति देने के लिए सुधारात्मक उपायों की पहचान की जा सके।

बैठक की शुरूआत में, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंडिया पोस्ट ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹17,546 करोड़ का महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। उन्होंने उल्लेख किया कि इंडिया पोस्ट इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है और चालू वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के दौरान पहले ही ₹10,155 करोड़ प्राप्त

कर चुका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रगति इंडिया पोस्ट के पार्सल और लॉजिस्टिक्स-संचालित संगठन बनने की ओर रणनीतिक बदलाव को दशार्ती है, जो ई-कॉमर्स, एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण की बढ़ती मांगों के अनुरूप है।

बिजनेस मीट 2025-26 की तीसरी तिमाही समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और डाक विभाग की सचिव सुश्री वंदिता कौल

तीसरी तिमाही के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने गौर किया कि हालांकि समग्र विकास के रुझान सकारात्मक हैं, लेकिन मुख्य कार्यक्षेत्रों—विशेष रूप से पार्सल, मेल और अंतर्राष्ट्रीय डाक—का प्रदर्शन अपेक्षा से कम रहा है। इस बात पर जोर देते हुए कि इंडिया पोस्ट का भविष्य का विकास काफी हद तक इसके कोर लॉजिस्टिक्स इंजन की मजबूती पर निर्भर करता है, केंद्रीय मंत्री ने जोर दिया कि पार्सल और डाक सेवाओं को अब "पूरी क्षमता के साथ" काम करना शुरू करना होगा। उन्होंने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे प्रमुख सर्किलों को—जो इंडिया पोस्ट के संभावित व्यवसाय का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा हैं—तत्काल सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को अपनाने का निर्देश दिया।

कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व पर आधारित झांकी होगी प्रदर्शित

नागरिकों के लिए संपत्ति के स्वामित्व के जरिए आत्मनिर्भरता एवं सम्मान की यात्रा पर डालती है प्रकाश

(जीएनएस)।

नई दिल्ली में 77वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर, इस वर्ष पंचायती राज मंत्रालय की झांकी 'स्वामित्व' योजना पर प्रकाश डालेगी, जो गणतंत्र दिवस 2026 समारोह के मुख्य विषयों— 'समृद्धि का मंत्रः आत्मनिर्भर भारत' और 'स्वतंत्रता का मंत्रः वंदे मातरम' के अनुरूप है। पंचायती राज मंत्रालय की यह झांकी 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई 'स्वामित्व' (ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण) योजना के परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रस्तुत करती है। यह रेखांकित करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय संपत्ति का कानूनी स्वामित्व किस प्रकार नागरिकों, पंचायतों और राष्ट्र के लिए सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता की नींव बनाता है।

झांकी के अगले हिस्से में, एक खुली हथेली पर टिका हुआ एक

सुनिर्मित ग्रामीण घर संपत्ति के स्वामित्व के माध्यम से प्राप्त आश्वासन और स्थिरता का प्रतीक है। 'आलता' से सजी एक महिला के हाथ के रूप में दिखाई गई हथेली, महिलाओं के सम्मान और घर के मालिकाना हक में उनके उचित स्थान को दशार्ती है। प्रवेश द्वार पर लगा एक पारंपरिक 'तोरण' समृद्धि का प्रतीक है, जबकि प्रमुखता से रखी गई घर की चाबियाँ स्वामित्व योजना के तहत कानूनी कब्जे और सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। पास में खेलते हुए बच्चे 'प्रॉपर्टी कार्ड' द्वारा सक्षम आत्मविश्वास, सुरक्षा और मजबूत पारिवारिक नींव को दशार्ते हैं।

झांकी का मध्य भाग एक लघु ग्रामीण परिवेश के माध्यम से 'स्वामित्व' योजना के क्रियान्वयन को प्रदर्शित करता है। इसमें ड्रोन-आधारित सर्वेक्षण, चूना मार्किंग और जमीनी स्तर की गतिविधियाँ सटीक मानचित्रण और सीमाओं के निर्धारण को दशार्ती हैं। अस्पष्ट भूमि अभिलेखों से आधिकारिक डिजिटल संपत्ति मानचित्रों की ओर यह बदलाव विवादों के समाधान, पंचायत नियोजन और बेहतर आजीविका के लिए भूमि के मौद्रिकरण में सहायक है। स्वच्छ सड़कें, हरियाली, जल निकाय और घर व्यवस्थित विकास और खुशहाली की तस्वीर पेश करते हैं। पिछले हिस्से में, झांकी योजना के प्रमुख परिणामों को दशार्ती है, जैसे कि शांतिपूर्ण विवाद समाधान, 'प्रॉपर्टी कार्ड' के माध्यम से बैंक ऋण तक पहुँच और प्रभावी स्थानीय शासन के प्रतीक के रूप में एक 'पंचायत भवन'। यह झांकी एक स्पष्ट संदेश देती है। सुरक्षित मालिकाना हक परिवारों को मजबूत करता है, सशक्त पंचायतों का निर्माण करता है और एक 'आत्मनिर्भर भारत' में योगदान देता है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सशस्त्र बलों में क्वांटम प्रौद्योगिकी के समावेशन से संबंधित पॉलिसी फ्रेमवर्क जारी किया

(जीएनएस)।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 22 जनवरी, 2026 को सशस्त्र बलों में क्वांटम प्रौद्योगिकी के समावेशन से संबंधित पॉलिसी फ्रेमवर्क जारी किया। यह एक व्यापक नीतिगत दस्तावेज है, जिसमें सशस्त्र बलों में क्वांटम प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन हेतु नीति और रोडमैप निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी के चार प्रमुख स्तंभों क्वांटम संचार, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी और क्वांटम सामग्री एवं उपकरण को तीनों सेनाओं में एकीकृत करना है। इस पहल का उद्देश्य तीनों सेनाओं को भविष्य के युद्धक्षेत्र की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाना और तेजी से परिवर्तित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में तकनीकी वर्चस्व प्राप्त करना है।

इस विजन डॉक्यूमेंट में क्वांटम प्रौद्योगिकियों के एकीकरण हेतु आवश्यक तालमेल स्थापित करने,

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के साथ सुदृढ़ संरेखण सुनिश्चित करने का स्पष्ट मार्ग परिभाषित किया गया है, जिसमें रक्षा बल एक अभिन्न घटक हैं। दस्तावेज में रक्षा बलों के भीतर इस विशिष्ट क्षेत्र के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक सांकेतिक रोडमैप और नीतिगत ढांचा भी निर्धारित किया गया है। यह विजन डॉक्यूमेंट तीनों सेनाओं के समन्वित प्रयासों के माध्यम से सशस्त्र बलों में अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकियों के समावेशन की ठोस आधारशिला प्रदान करेगा।

यह विजन डॉक्यूमेंट रक्षा परिप्रेक्ष्य से इन विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने की बढ़ती आवश्यकता पर बल देता है। यह असैन्य-सैन्य समेकन के माध्यम से हासिल किए जाने वाले मील के पत्थरों एवं लक्ष्यों को रेखांकित करता है, जिसमें विभिन्न सरकारी क्षेत्रों के सदस्यों से सहयोग प्राप्त समर्पित शासी निकाय शामिल हैं। यह रूपरेखा भविष्य के युद्धक्षेत्र में तकनीकी श्रेष्ठता सुनिश्चित करने हेतु इन प्रौद्योगिकियों के प्रभावी आत्मसात में संयुक्तता और एकीकरण की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता को भी स्पष्ट रूप से उजागर करती है।

रेल-पर-ट्रक: भारतीय रेलवे के समर्पित माल ढुलाई गलियारे द्वारा संचालित एक रणनीतिक परिवहन बदलाव

सड़क दक्षता को रेल दक्षता के साथ मिलाकर; रेल-पर-ट्रक, बहु-मॉडल एकीकरण के माध्यम से लंबी दूरी के माल परिवहन को अनुकूलित करता है, उत्सर्जन, भीड़भाड़ और लॉजिस्टिक लागत को कम करता है

(जीएनएस)।

जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और खपत में विविधता आ रही है, माल परिवहन में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे सड़क परिवहन, ईंधन उपयोग और वायु गुणवत्ता पर दबाव बढ़ा है। इसे हल करने के लिए, भारतीय रेलवे ने अपने दूरदर्शी समर्पित माल ढुलाई गलियारा (डीएफसी) पहल के माध्यम से अभिनव रेल-पर-ट्रक (टीओटी) सेवा शुरू की है। यह योजना भारतीय रेलवे की दीर्घकालिक माल परिवहन परिवर्तन रणनीति के हिस्सा के रूप में बनाई गई थी, डीएफसी नेटवर्क वह

ढांचा प्रदान करता है जो नई पीढ़ी की बहु-मॉडल लॉजिस्टिक्स को सक्षम बनाता है।

टीओटी भारतीय रेलवे के समर्पित माल ढुलाई गलियारा कार्यक्रम के तहत विकसित विद्युत रेल अवसंरचना की दक्षता और पर्यावरणीय लाभों के साथ सड़क परिवहन के लचीलेपन को जोड़ता है। इस सेवा के तहत माल से लदे ट्रकों को विशेष रूप से संशोधित फ्लैट वैगनों पर समर्पित माल ढुलाई गलियारा के माध्यम से ले जाया जाता है। ट्रक लंबे और भारी यातायात वाली राजमार्ग यात्रा से बचते हैं और मुख्य मार्ग के लिए रेल द्वारा यात्रा करते हैं। इसके बाद वे केवल प्रथम-मील और अंतिम-मील तक छोटी सड़क यात्राएं पूरी करते हैं।

किफायती लेकिन भरोसेमंद

वर्तमान में, टीओटी सेवा पश्चिमी डीएफसी नेटवर्क पर न्यू रेवाड़ी और न्यू पालनपुर के बीच संचालित होती है। जैसे-जैसे अवसंरचना का विकास होगा, इसका विस्तार अतिरिक्त खंडों तक किया जाएगा। न्यू पालनपुर-न्यू रेवाड़ी कॉरिडोर पर, यह सेवा लगभग 636 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो सड़क मार्ग से लगभग 30 घंटे लगने वाले सफर को टीओटी सेवा के माध्यम से लगभग 12 घंटे में पूरा कर देती है।

स्वास्थ्य और किफायती इलाज का संगम: भारत एक वैश्विक चिकित्सा यात्रा गंतव्य के रूप में उभर रहा है

आयुष वीजा और आयुष गुणवत्ता मार्क सहित नीति-प्रेरित पहलें, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को आगे बढ़ा रही हैं

(जीएनएस)।

भारत मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) के लिए सबसे तेजी से बढ़ते गंतव्यों में से एक के रूप में उभर रहा है और यह विश्व स्तरीय चिकित्सा अवसंरचना, उच्च कुशल स्वास्थ्य पेशेवरों तथा किफायती उपचार को चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों एवं समग्र कल्याण में देश की विशिष्ट क्षमता के साथ जोड़ता है।

जटिल शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं से लेकर दीर्घकालिक स्वास्थ्य उपचारों तक, भारत आज एक एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली प्रदान कर रहा है। यह विश्वास अंतर्राष्ट्रीय मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती इलाज के लिए भारत की ओर तेजी से आकर्षित कर रहा है। भारत में वैश्विक स्तर पर मानकीकृत अस्पतालों में प्रसिद्ध विशेषज्ञों द्वारा किफायती उपचार प्रदान किए जाते हैं, जबकि पारंपरिक आयुष प्रणालियां देश के चिकित्सा पर्यटन आकर्षण में एक विशिष्ट निवारक और स्वास्थ्य संबंधी आयाम जोड़ती हैं।

वन अर्थ वन हेल्थ-एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया 2023 में अपने संबोधन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए किफायती और विश्वसनीय चिकित्सा यात्रा के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा, 'भारत स्वस्थ पृथ्वी के लिए किफायती चिकित्सा यात्रा और स्वास्थ्य कार्यबल की गतिशीलता को महत्वपूर्ण मानता है ह्व माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, 'हजारों वर्षों से, स्वास्थ्य के प्रति भारत का दृष्टिकोण समग्र रहा है। हमारे पास निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य की एक महान परंपरा है। योग और ध्यान जैसी प्रणालियां अब वैश्विक आंदोलन बन चुकी हैं। ये प्राचीन भारत की आधुनिक दुनिया को दी गई देन हैं। इसी प्रकार, हमारी आयुर्वेद प्रणाली स्वास्थ्य का एक संपूर्ण अनुशासन है। यह स्वास्थ्य के शारीरिक और मानसिक दोनों पहलुओं का ध्यान रखती है। दुनिया तनाव और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के समाधान खोज रही है। भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों में कई समाधान उपस्थित हैं। हमारा पारंपरिक आहार, जिसमें बाजरा शामिल है, खाद्य सुरक्षा और पोषण में भी सहायक हो सकता है ह्व

वैश्विक विश्वास और गुणवत्ता आश्वासन को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में 19 दिसंबर 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम में 'आयुष गुणवत्ता मार्क' का शुभारंभ किया। आयुष गुणवत्ता मार्क आयुष उत्पादों और सेवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप आश्वासन प्रारूप प्रदान करता है, जिससे प्रामाणिक और मानकीकृत स्वास्थ्य देखभाल की खोज करने वाले अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के बीच विश्वास और मजबूत होता है।

भारत के एकीकृत किफायती चिकित्सा यात्रा दृष्टिकोण को सुदृढ़ करते हुए, पारंपरिक चिकित्सा को पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के साथ जोड़ते हैं। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव ने इस बात पर बल दिया कि भारत की क्षमता उसके एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण में निहित है। मंत्री महोदय ने कहा कि किफायती चिकित्सा यात्रा केवल किफायती ही नहीं है, बल्कि विश्वास, गुणवत्ता और परिणामों से भी जुड़ी है। भारत की आयुष प्रणालियां समय-परीक्षित, साक्ष्य-आधारित समाधान प्रदान करती हैं जो पारंपरिक चिकित्सा के पूरक हैं और समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए वैश्विक मांग को पूरा करती हैं।

वैश्विक रोगियों को आकर्षित करने में विश्वसनीयता और मानकीकरण के महत्व का उल्लेख करते हुए आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि वैश्विक विकास को बनाए रखने के लिए विश्वसनीयता और मानकीकरण महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि पारंपरिक और स्वास्थ्य-आधारित देखभाल में बढ़ती अंतरराष्ट्रीय रुचि को देखते हुए भारत गुणवत्ता आश्वासन, डिजिटल सुविधा और अंतरराष्ट्रीय मानकों के माध्यम से अपने मेडिकल वैल्यू ट्रैवल ढांचे को मजबूत कर रहा है। यह एकीकृत दृष्टिकोण भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक स्वास्थ्य सेवा गंतव्य के रूप में स्थापित कर रहा है।

आंकड़े इस बढ़ती गति को दशार्ते हैं। भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय रोगियों की संख्या 2020 में 1,82,945 से बढ़कर 2024 में 6,44,387 हो गई। हाल के वर्षों में, योग, आयुर्वेद और स्वास्थ्य-आधारित चिकित्सा पद्धतियों ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे भारत समग्र, साक्ष्य-आधारित देखभाल के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित हो चुका है।

सीएक्यूएम ने एक्यूआई में सुधार को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर से चरण-3 के प्रतिबंध हटाए

(जीएनएस)।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) पर उपसमिति ने हवा की क्वालिटी में सुधार और मौसम के सकारात्मक रुझानों के मद्देनजर दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चरण-3 के प्रतिबंधों को 22 जनवरी 2026 को तुरंत प्रभाव से हटाने का फैसला किया।

उपसमिति ने दिल्ली के औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में गिरावट के बाद 16.01.2026 को ग्रैप का चरण-3 लागू कर दिया था। इसके बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता में बेहतरी का रुझान देखने को मिला। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दैनिक एक्यूआई बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार सुधरते हुए 20.01.2026 को 378 से घट कर 21.01.2026 को 330 और 22.01.2026 को 322 हो गया। सुधार के इस रुझान तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के वायु गुणवत्ता और मौसम के अनुमानों को देखते हुए सीएक्यूएम की उपसमिति ने आज अपनी बैठक में स्थिति की समीक्षा की।

उपसमिति ने इस बात पर गौर किया कि दिल्ली में एक्यूआई मौसम की अनुकूल स्थितियों की बदौलत सुधर रहा है। आईएमडी और आईआईटीएम के अनुमानों के अनुसार अगले कुछ दिनों में एक्यूआई 'मध्यम' से 'खराब' श्रेणी में रहेगा। ग्रैप के चरण-3 के प्रतिबंध बड़ी संख्या में हितधारकों और आम नागरिकों को प्रभावित करते हैं। इन प्रतिबंधों की अवरोधक प्रकृति को देखते हुए ग्रैप पर सीएक्यूएम की उपसमिति ने समूचे दिल्ली-एनसीआर में मौजूदा कार्यक्रम के चरण-3 के तहत सभी कदमों को तुरंत प्रभाव से हटाने का फैसला किया।

ग्रैप के मौजूदा कार्यक्रम (नवंबर, 2025) के अंतर्गत चरण-2 और चरण-1 के सभी उपाय समूचे दिल्ली-एनसीआर में लागू रहेंगे। संबंधित एजेंसियां इनका क्रियान्वयन, निगरानी और समीक्षा करेंगी ताकि आने वाले दिनों में वायु की गुणवत्ता में गिरावट नहीं आए। एजेंसियां चरण-2 और चरण-1 के अंतर्गत उपायों के अमल पर कड़ी नजर रखते हुए उन्हें सख्ती से लागू कराएंगी ताकि दिल्ली-एनसीआर में चरण-3 के प्रतिबंध फिर से लागू करने की जरूरत नहीं पड़े।

भवन निर्माण और गिराने वाले परियोजना स्थल आदि, जिन्हें विभिन्न वैधानिक निदेर्शों, नियमों, दिशा-निदेर्शों आदि के उल्लंघन/गैर-अनुपालन के कारण विशेष रूप से बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, वे किसी भी परिस्थिति में, आयोग के विशिष्ट आदेश के बिना अपना संचालन फिर से शुरू नहीं करेंगे।

हालांकि ग्रेप के तीसरे चरण को हटाया जा रहा है, लेकिन सर्दियों के मौसम को देखते हुए जब मौसम की स्थिति हमेशा अनुकूल नहीं हो सकती है और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का स्तर और खराब न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों से अनुरोध है कि वे ग्रेप की वर्तमान अनुसूची के चरण-क्क और चरण-क के तहत नागरिक चार्टर का सख्ती से पालन करें।

उप-समिति वायु गुणवत्ता के हालात पर पैनी नजर रखेगी और दिल्ली में वायु गुणवत्ता तथा भारतीय आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा उपलब्ध कराइ गई मौसम संबंधी जानकारी एवं एक्यूआई के पूवार्नुमान के आधार पर, आगे के उचित निर्णयों के लिए समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करेगी।

ग्रेप की वर्तमान अनुसूची (नवंबर 2025) आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) में भारत के प्रति दुनिया के बढ़ते विश्वास को रेखांकित किया

बैठक के दौरान उच्च स्तरीय विचार-विमर्श हुआ, जिसमें दुनिया भर के प्रमुख औद्योगिक समूहों ने भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को विस्तार देने की गहरी इच्छा प्रकट की

श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत की क्रिटिकल मिनरल्स वैल्यू चेन को सुरक्षित करने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की अहम भूमिका

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र के वैश्विक नेतृत्वकताओं को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया

(जीएनएस)।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव ने दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) में अपनी बैठकों के दौरान भारत के प्रति बढ़ते वैश्विक विश्वास और एक भरोसेमंद वैल्यू-चेन पार्टनर के रूप में भारत के उभरने पर

विशेष जोर दिया।

श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठकें भारत की ग्रोथ स्टोरी को और मजबूती प्रदान करती हैं। उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रौद्योगिकी, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और उभरते क्षेत्रों में भारत के साथ साझेदारी करने के लिए ग्लोबल लीडर्स की ओर से निरंतर रुचि दिखाई जा रही है।

चर्चा के दौरान, टेमासेक के अध्यक्ष श्री तेओ ची हियान ने भारत में टेमासेक की मौजूदगी बढ़ाने में रुचि व्यक्त की। उन्होंने भारत के फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे के साथ-साथ डीप-टेक स्टार्टअप्स में निवेश करने की सिंगापुर की प्रतिबद्धता को दोहराया। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और साइबर सुरक्षा क्षेत्र के दिग्गजों के साथ हुई बातचीत भारत की एक भरोसेमंद वैल्यू-चेन पार्टनर के रूप में बढ़ती साख को दर्शाती है।

श्री अश्विनी वैष्णव ने रेखांकित किया कि दावोस में हुई सभी बैठकों में भारत के प्रति वैश्विक विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। मार्सक शिपिंग, पोर्ट और रेलवे के लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है और सेमीकंडक्टर सामग्री के क्षेत्र में भी सहयोग कर रहा है। वहीं, हनीवेल भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण में भागीदारी कर रहा है और देश में अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के विस्तार में गहरी रुचि व्यक्त की है।

श्री वैष्णव ने डब्ल्यूईएफ में गूगल डीपमाइंड के सीईओ और सह-संस्थापक श्री डेमिस हसाबिस और ओपनएआई के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर श्री क्रिस लेहने से भी मुलाकात की। श्री वैष्णव ने वैश्विक कल्याण के लिए एआई को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका पर चर्चा की।

केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई-क्श के तहत जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के लिए 10,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी

पहले से अलग-थलग पड़े लगभग 3,270 बस्तियों को कनेक्टिविटी और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होगी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-क्श के तहत एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है, जो विकसित भारत के लिए ग्रामीण विकास विभाग की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है।

दूरस्थ पहाड़ियों से लेकर ग्रामीण समुदायों के मध्य तक फैली ये सड़कें मात्र अवसंरचना में सुधार का प्रतीक नहीं हैं; बल्कि ये प्रगति के लिए महत्वपूर्ण मार्ग हैं, जो अनेक अवसर खोलती हैं और समावेशी विकास को बढ़ावा देती हैं। इन सड़कों के निर्माण से लगभग 3,270 पहले से अलग-थलग पड़े क्षेत्रों को कनेक्टिविटी और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच मिलेगी। ऐसा अनुमान है कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बेहतर आजीविका तक पहुंच प्रदान करके ये सड़कें ग्रामीण जीवन को गहराई से बदल देंगी और एक विकसित भारत की नींव को मजबूत करेंगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-क्श के तहत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 250 से अधिक, विशेष श्रेणी के क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची श, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, मरुस्थलीय क्षेत्र) में 25,000 असंबद्ध बस्तियों और वाम उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 100 से अधिक आबादी वाली बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान की जानी है।

इस योजना का उद्देश्य उन बस्तियों को 62,500 किलोमीटर लंबी, हर मौसम में उपयोग योग्य सड़कें उपलब्ध कराना है जो अभी तक आपस में जुड़ी नहीं हैं। इन सड़कों के साथ-साथ आवश्यक पुलों का निर्माण भी किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर, 2024 को ग्रामीण विकास विभाग के वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना -क्श (पीएमजीएसवाई-क्श) के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस योजना का कुल परिव्यय 70,125 करोड़ रुपये (केंद्र सरकार का हिस्सा 49,087.50 करोड़ रुपये और राज्य सरकार का हिस्सा 21,037.50 करोड़ रुपये) है।

ईसीआईएनईटी डिजिटल प्लेटफॉर्म को आईआईसीडीईएम-2026 में लॉन्च किया गया

(जीएनएस)।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आज भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन (आईआईसीडीईएम) 2026 में चुनाव संबंधी सभी सूचनाओं और सेवाओं के लिए अपने एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म ईसीआईएनईटी को लॉन्च किया । यह तीन दिवसीय सम्मेलन (21-23 जनवरी, 2026) नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है।

ईसीआईएनईटी की परिकल्पना भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त (ईसी) डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर की थी और इसके विकास की घोषणा मई 2025 में की गई थी।

इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्य आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा कि एउक्थएळ को कानून के पूर्ण अनुपालन में विकसित किया गया है और यह 22 अनुसूचित भाषाओं और अंग्रेजी में उपलब्ध है। उन्होंने विश्व के सभी ईएमबी को अपने-अपने कानूनों और भाषाओं के अनुसार, अपने-अपने देशों के लिए इसी तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने में भारत के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव दिया।

चुनाव आयोग के डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कहा कि ईसीआईएनईटी, ईएमबी में विश्वास बढ़ाने का एक बेहतरीन साधन है क्योंकि यह अधिक पारदर्शिता लाता है और सभी कार्यों की निगरानी में मदद करता है तथा त्वरित निर्णय लेने और सूचना प्रसार को सक्षम बनाता है।

चुनाव आयोग के डॉ. विवेक जोशी ने कहा कि यह सम्मेलन ईएमबी को प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचारों को अपनाने के संबंध में वैश्विक प्रथाओं से सीखने और उनसे लाभ उठाने का अवसर प्रदान करेगा।

अपने प्रस्तुतीकरण के दौरान, सूचना प्रौद्योगिकी महानिदेशक डॉ. सीमा खन्ना ने कहा कि साइबर सुरक्षा ईसीआईएनईटी के प्रमुख स्तंभों में से एक है। उन्होंने कहा कि तकनीक अब केवल सहायक भूमिका नहीं बल्कि एक रणनीतिक सहायक है। उन्होंने आगे कहा कि ईसीआईएनईटी चुनावों में पारदर्शिता, दक्षता, विश्वसनीयता और जनविश्वास को बढ़ावा देता है।

एउक्थएळ दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी सेवा मंच है, जो भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र की सभी चुनावी सेवाओं को एक सहज अनुभव में एकीकृत करता है। यह भारत निर्वाचन आयोग के 40 से अधिक ऐप्स और पोर्टल्स को शामिल करता है। यह मंच भारत के संविधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951, मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 और चुनाव संचालन नियम, 1961 के पूर्ण अनुपालन में विकसित किया गया है।

ईसीआईएनईटी नागरिकों, उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और चुनाव अधिकारियों को जोड़ता है और मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूची खोज, अपने आवेदन को ट्रैक करना, अपने उम्मीदवार को जानना, चुनाव अधिकारियों से जुड़ना, बीएलओ के साथ कॉल बुक करना, ई-ईपीआईसी डाउनलोड, मतदान रुझान, शिकायत निवारण आदि जैसी प्रमुख सेवाओं को एक सुरक्षित मंच पर लाता है।

2025 के बिहार विधानसभा चुनावों और विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के दौरान बीटा संस्करण का सफल परीक्षण किया गया, जिससे चुनाव आयोग को नागरिकों को बेहतर चुनावी सेवाएं प्रदान करने और एक बटन के क्लिक पर चुनाव संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध कराने में मदद मिली। लॉन्च से पहले, प्लेटफॉर्म को अंतिम रूप देने से पहले नागरिकों से सुझाव मांगे गए थे।

बीटा रिलीज के बाद से, ईसीआईएनईटी ने अब तक 10 करोड़ से अधिक पंजीकरण प्रपत्रों को संसाधित किया है, यानी प्रतिदिन औसतन 2.7 लाख प्रपत्र। इस प्लेटफॉर्म पर 11 लाख से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी (इछड) पंजीकृत हैं। एसआईआर के दौरान अब तक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 150 करोड़ से अधिक दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। ईसीआईएनईटी जमीनी स्तर के अधिकारियों की निगरानी के लिए एक सुगम तंत्र भी प्रदान करता है।

भारत का विद्युत पारेषण नेटवर्क 5 लाख सर्किट किलोमीटर से अधिक हुआ

अप्रैल 2014 से पारेषण नेटवर्क में 71.6 प्रतिशत की वृद्धि

गैर-जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न बिजली की बढ़ती मात्रा की निकासी में सहायता के लिए अतिरिक्त 67000 सर्किट किलोमीटर की परियोजनाएं जारी

(जीएनएस)।

भारत के राष्ट्रीय विद्युत पारेषण नेटवर्क ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 5 लाख सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) से अधिक पारेषण लाइनें (220 केवी और उससे ऊपर) और 1,407 जीवीए की रूपांतरण क्षमता (220 केवी और उससे ऊपर) शामिल हैं।

विश्व के सबसे बड़े सिंक्रोनस राष्ट्रीय ग्रिड ने 14 जनवरी 2026 को यह उपलब्धि हासिल की, जब राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए भादला द्वितीय से सीकर द्वितीय सबस्टेशन तक 765 केवी की 628 सी.के.एम लंबी ट्रांसमिशन लाइन चालू की गई। इस ट्रांसमिशन लाइन के चालू होने से भादला, रामगढ़ और फतेहगढ़ सौर ऊर्जा परिसर के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से अतिरिक्त 1100 मेगावाट बिजली की निकासी संभव हो सकेगी।

अप्रैल 2014 से, देश के पारेषण नेटवर्क में 2.09 लाख सीकेएम (220 केवी और उससे ऊपर) पारेषण लाइनों के जुड़ने से 71.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे (220 केवी और उससे ऊपर) रूपांतरण क्षमता में 876 जीवीए की वृद्धि हुई है। अंतर-क्षेत्रीय विद्युत हस्तांतरण क्षमता, जो अब 1,20,340 मेगावाट है, ने क्षेत्रों के बीच बिजली के निर्बाध हस्तांतरण को सक्षम बनाया है, जिससे "एक राष्ट्र-एक ग्रिड-एक आवृत्ति" की परिकल्पना सफलतापूर्वक साकार हुई है।

वर्तमान में कार्यान्वित हो रही अंतरराज्यीय पारेषण परियोजनाओं से लगभग 40,000 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइनें और 399 जीवीए की रूपांतरण क्षमता जुड़ जाएगी। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वित हो रही अंतरराज्यीय पारेषण परियोजनाओं से 27,500 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइनें और 134 जीवीए की रूपांतरण क्षमता और जुड़ने की उम्मीद है, जिससे ग्रिड की विश्वसनीयता और बिजली निकासी क्षमता में और वृद्धि होगी।

पारेषण क्षमता में वृद्धि से गैर-जीवाश्म ईंधन से होने वाले बिजली उत्पादन में हो रही वृद्धि को दूर करने में सहायता मिलेगी, जिसका लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचना है।

5,00,000 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइनों की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि पूरे देश में विश्वसनीय, किफायती और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण में तीव्र वृद्धि का समर्थन करने की दिशा में सरकार के निरंतर प्रयासों को दशार्ता है।

पश्चिमी सिंहभूम में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जारी जॉइंट ऑपरेशन में ₹1 करोड़ के कुख्यात इनामी नक्सली सेंट्रल कमेटी मेंबर 'अनल उर्फ पतिराम मांझी' और 15 अन्य नक्सलियों के मारे जाने से नक्सलमुक्त अभियान

दशकों से भय और आतंक के पर्याय रहे नक्सलवाद को हम 31 मार्च 2026 से पहले समाप्त करने के लिए संकल्पित हैं

मेरी पुनः शेष बचे नक्सलियों से अपील है कि हिंसा, आतंक और हथियारों से जोड़ने वाली विचारधारा को छोड़ विकास और विश्वास की मुख्यधारा से जुड़ें

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में ₹1 करोड़ का कुख्यात इनामी नक्सली सेंट्रल कमेटी मेंबर 'अनल उर्फ पतिराम मांझी' और 15 अन्य नक्सलियों के मारे जाने पर कहा कि इससे नक्सलमुक्त अभियान को बड़ी सफलता मिली।

प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा 'आज पश्चिमी सिंहभूम में उफ्छक्र और झारखंड पुलिस द्वारा चल रहे एक जॉइंट ऑपरेशन में ₹1 करोड़ का कुख्यात इनामी नक्सली सेंट्रल कमेटी मेंबर 'अनल उर्फ पतिराम मांझी' और 15 अन्य नक्सलियों के अब तक एनकाउंटर से नक्सलमुक्त अभियान को बड़ी सफलता मिली। दशकों से भय और आतंक के पर्याय रहे नक्सलवाद को हम 31 मार्च 2026 से पहले समाप्त करने के लिए संकल्पित हैं। मेरी पुनः शेष बचे नक्सलियों से अपील है कि हिंसा, आतंक और हथियारों से जोड़ने वाली विचारधारा को छोड़ विकास और विश्वास की मुख्यधारा से जुड़ें।

पंजाब में केजरीवाल और भगवंत मान सरकार की स्वास्थ्य गारंटी पूरी - इसुदान गढ़वी

अब पंजाब के 65 लाख परिवारों को बिना शर्त और बिना भेदभाव के 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा - इसुदान गढ़वी

जिन शानदार व महंगे अस्पतालों में अमीर इलाज कराते हैं, अब वहां गरीब भी इलाज करा सकेगा - इसुदान गढ़वी

'आपह्न के मुख्यमंत्री जनता के लिए हेल्थ कार्ड बना रहे हैं और इनके मुख्यमंत्री विदेश में सैर-सपाटा कर रहे - इसुदान गढ़वी

देश के इतिहास में यह पहली ऐसी योजना है जो सच में सबके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देती है - इसुदान गढ़वी

मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली और महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने वाला पंजाब देश का पहला राज्य - इसुदान गढ़वी

कांग्रेस में सीएम बनने के लिए सभी आपस में लड़ रहे हैं, इन पार्टियों को लूटने के लिए सिर्फ सत्ता चाहिए - इसुदान गढ़वी

सिर्फ आम आदमी पार्टी ही पंजाब को सुरक्षित भविष्य दे सकती है - इसुदान गढ़वी

यह दुनिया की इकलौती स्कीम है जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर और हृदय रोग का भी मुफ्त इलाज होगा - इसुदान गढ़वी

गुजरात/अहमदाबाद

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत सिंह मान की ओर से पंजाब को मुफ्त इलाज की दी गई गारंटी भी पूरी हो गई। इस अवसर पर, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने कहा कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा दी गई मुफ्त इलाज की गारंटी अब पूरी तरह साकार हो चुकी है। अब पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। मोहाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरूआत के साथ ही पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जहां मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली और महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा एक साथ दी जा रही है।

जिन शानदार और महंगे निजी अस्पतालों में अब तक केवल अमीर लोग इलाज कराते थे, अब वहां गरीब किसान, मजदूर और रिक्शेवाला भी बिना पैसे के इलाज करा सकेगा। यह देश के इतिहास की पहली ऐसी योजना है, जो सच में सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देती है।

प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ कुछ मुख्यमंत्री अपने परिवारों के साथ विदेशों में घूम रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री रात-दिन जनता के लिए हेल्थ कार्ड बनाने में लगे हैं। यही फर्क है उनकी सैर-सपाटे की राजनीति और आम आदमी पार्टी की सेवा की राजनीति में। कांग्रेस और अन्य दलों में मुख्यमंत्री बनने की होड़ मची हुई है। इन पार्टियों को जनता की नहीं, सिर्फ सत्ता की चिंता है ताकि वे लूट सकें। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही पंजाब और पंजाबियों को सुरक्षित भविष्य दे सकती है।

उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने जनता की असली चिंता नहीं की। आज जो ऐतिहासिक काम पंजाब में हो रहा है, वह आजादी के बाद बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यह दौर पंजाब के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।

चुनावी वादों का जिक्र करते हुए इसुदान गढ़वी ने कहा कि 'केजरीवाल की गारंटी' को मजाक समझने वाले आज देख रहे हैं कि मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज सब कुछ संभव है। सरकार ने न केवल वादे पूरे किए, बल्कि स्वास्थ्य ढांचे को पूरी तरह बदल दिया है।

उन्होंने बताया कि पंजाब में बीते चार वर्षों में 1000 से अधिक मोहल्ला क्लीनिक बनाए गए हैं, 500 और बन रहे हैं और अगले चार-पांच महीनों के अंदर हर गांव में 2500 'पिंड क्लीनिक' बनने वाले हैं। जो काम पिछली सरकारों ने 75 साल में किया, उससे शायद 10 गुना काम इस सरकार ने 4 साल में करके दिखा दिया है।

इसुदान गढ़वी ने कहा कि अब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी नहीं है, मशीनें चालू हैं, मुफ्त दवाइयां मिल रही हैं और सरकारी अस्पताल निजी अस्पतालों से बेहतर बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना उन किसानों और मजदूरों के लिए वरदान है, जिन्हें बीमारी में अपनी जमीन, गहने और घर बेचने पड़ते थे। अब किसी को इलाज के लिए कर्ज.या जमीन गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने बताया कि यह 10 लाख रुपये का बीमा सभी 65 लाख परिवारों के लिए है - अमीर-गरीब, सभी धर्मों और जातियों के लिए, बिना किसी शर्त के। न कोई कार्ड का रंग, न कोई भेदभाव। बस हेल्थ कार्ड दिखाइए और इलाज पाइए। उन्होंने नशे और अपराध के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि पहली बार किसी सरकार ने नशा तस्करों और गैंगस्टरों पर सख्त कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाई है। जब पंजाब के बच्चे नशे से मर रहे थे, तब विपक्ष को मानवाधिकार याद नहीं आए। आज अपराधियों पर कार्रवाई होने पर ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं।

इसुदान गढ़वी ने कहा कि आम आदमी पार्टी कोई अमीरों की पार्टी नहीं है। यह कुदरत का करिश्मा है कि आम लोगों की यह पार्टी सत्ता में आई और जनता के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस योजना का भी विरोध करेगा, लेकिन यह योजना सबके लिए है - 'आपह्न सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया और न ऐसी कोई शर्त ही रखी कि कांग्रेसियों या अकालियों का इलाज नहीं होगा। सबका इलाज होगा, भगवान सबको खुश रखे।

अंत में इसुदान गढ़वी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भारत देश के परिवारों के भविष्य की चिंता करती है। हमें सत्ता नहीं, सेवा चाहिए। जनता का विश्वास और प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

आम आदमी पार्टी गुजरात

शांति की जागी उम्मीद: UAE में रूस-US-यूक्रेन की पहली त्रिपक्षीय बैठक कल, जेलेंस्की ने की पुष्टि

(जीएनएस)।

यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच तकनीकी स्तर की पहली त्रिपक्षीय बैठक 23 और 24 जनवरी को संयुक्त अरब अमीरात (वअए) में आयोजित की जाएगी। इसकी घोषणा यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच (हएऋ) के दौरान की।

जेलेंस्की ने बताया कि यह तीनों देशों के बीच पहली ऐसी बैठक है और उन्हें उम्मीद है कि यह युद्ध समाप्त करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा, "कल और परसों हमारी त्रिपक्षीय बैठक होगी, यह संवाद न होने से बेहतर है।" यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ एक घंटे की बैठक के बाद आई, जिसे ट्रम्प ने "अच्छा" बताया था।

जेलेंस्की ने बैठक को लेकर क्या उम्मीद जताई?

जेलेंस्की ने आगे जानकारी दी कि यूक्रेनी टीम ने गुरुवार को अमेरिकियों से मुलाकात की, जिसके बाद अमेरिकी टीम रूस के लिए रवाना होगी। उन्होंने अपने अजीबोगरीब अंदाज में कहा, "हमारे लोग आज अमेरिकियों से मिल रहे हैं, फिर अमेरिकी कल, आज रात - कब, मुझे नहीं पता, शायद पुतिन सो रहे हैं, आपने कहा था कि कोई नहीं जानता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है।"

क्या यह घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात के बाद हुई?

जेलेंस्की ने इस बात पर जोर दिया कि "रूसी लोगों को समझौते के लिए तैयार रहना चाहिए"। उन्होंने स्पष्ट किया, "यूक्रेन ही नहीं, सभी को तैयार रहना चाहिए, और यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हम देखेंगे कि परिणाम क्या होंगे।" हालांकि, यूक्रेनी नेता ने बातचीत के फॉर्मेट या अधिकारियों के सीधे संवाद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता की भी आलोचना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि महाद्वीप को अपनी स्वयं की एकीकृत सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकता है जो वास्तव में उसकी रक्षा कर सकें। उनका मानना है कि वर्तमान निर्भरता अस्थिर है।

जेलेंस्की के अनुसार, "यूरोप को संयुक्त सशस्त्र बलों की आवश्यकता है, ऐसी ताकतों की जो वास्तव में आज यूरोप की रक्षा कर सकें। यूरोप केवल इस विश्वास पर निर्भर करता है कि यदि खतरा आता है, तो नाटो कार्रवाई करेगा, लेकिन किसी ने वास्तव में गठबंधन को कार्रवाई में नहीं देखा है।"

उन्होंने उस स्थिति पर भी सवाल उठाया जब अमेरिका मदद नहीं करेगा, यह कहते हुए कि नाटो का अस्तित्व इस विश्वास पर टिका है कि संयुक्त राज्य अमेरिका कार्रवाई करेगा और अलग नहीं खड़ा रहेगा। जेलेंस्की ने चेतावनी दी, "लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या? मेरा विश्वास करें, यह सवाल हर यूरोपीय नेता के दिमाग में छाया हुआ है।"

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने पान मसाला एवं गुटखा की पैकेजिंग में बायोप्लास्टिक के उपयोग पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक की अध्यक्षता की

(जीएनएस)।

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए), प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने 'पान मसाला एवं गुटखा की पैकिंग एवं भंडारण के लिए पाउच में बायोप्लास्टिक के उपयोगह्न पर प्रगति की समीक्षा करने एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय हितधारक परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में डॉ. परविंदर मैनी, पीएसए कार्यालय के वैज्ञानिक सचिव; डॉ. राजेश गोखले, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव; श्री तन्मय कुमार, सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; श्री राजित पुन्हानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई); उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग, भारतीय

मानक ब्यूरो (बीआईएस) और भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) के वरिष्ठ अधिकारियों सहित शिक्षा जगत, उद्योग जगत और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

बैठक में पाउच पैकेजिंग के लिए उपयुक्त जैव-अपघटनशील सामग्रियों की पहचान करने के उद्देश्य से चल रही राष्ट्रीय पहलों एवं अनुसंधान प्रयासों की समीक्षा की गई। अपने आरंभिक संबोधन में, पीएसए प्रोफेसर सूद ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और उपभोक्ता मामलों के विभाग के साथ पहले हुई चचाओं का सारांश प्रस्तुत किया और पान मसाला एवं गुटखा पैकेजिंग के लिए एक स्पष्ट, समयबद्ध कार्य योजना को अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया।

डॉ. गोखले ने पाउच प्लास्टिक की कम अपघटनशीलता के कारण होने वाली महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौती पर बल दिया। उन्होंने पॉलिलैक्टिक एसिड (पीएलए) को एक आशाजनक जैव-अपघटनशील विकल्प के रूप में पहचान की, जिसकी लागत कम है और सरकार, उद्योग एवं शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी के साथ समन्वित, समयबद्ध कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।

श्री तन्मय कुमार ने कहा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जैवप्लास्टिक की मौजूदा परिभाषा की समीक्षा कर रहा है और जैव-अपघटनशील पदार्थों की स्पष्ट परिभाषा तैयार करने की प्रक्रिया में है, जिससे बीआईएस को मानकीकृत परीक्षण प्रोटोकॉल विकसित करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक समान और तकनीकी रूप से सुदृढ़ संरचना तैयार करने के लिए इस प्रकार के परामर्श आवश्यक हैं। श्री राजित पुन्हानी ने इस बात पर बल दिया कि जैव-अपघटनशील पैकेजिंग की लागत उत्पाद लागत से कम होनी चाहिए, साथ ही स्वाद एवं सुगंध की सुरक्षा सुनिश्चित करना, एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित माइग्रेशन सीमाओं का सख्ती से पालन करना और पैकेजिंग की सभी परतों से प्लास्टिक और एल्यूमीनियम फॉयल

24 जनवरी को लखनऊ में 'उत्तर प्रदेश दिवस' समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करेंगे : श्री अमित शाह

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह शनिवार, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 'उत्तर प्रदेश दिवस' समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करेंगे। लखनऊ स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह 'एक जनपद - एक व्यंजन' योजना की शुरूआत करेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक जनपद/जिले के विशिष्ट पारंपरिक व्यंजन को चिह्नित कर उन्हें गुणवत्ता, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़ा जाएगा, ताकि स्थानीय स्वाद की केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान बन सके।

'उत्तर प्रदेश दिवस' समारोह के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का भी शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की उट वश्अ (मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान) योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनपदों को पुरस्कार देंगे और साथ ही, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 का वितरण करेंगे।